pany in the name of Spectrum Power Generation Company has already been established. The promoter agreement is under finalisation. Discussions by the Joint Sector company with Gas Authority of India Limited (GAIL) for a Fuel Supply Agreement and with Andhra Pradesh Electricity Board for a Power Purchase Agreement are in progress.

पावर ग्रिड कारपोरेशन को योजना को पूरा किए जाने के दौरान पारेषण में विद्युत की हानि

991. डा. **जितेन्द्र कुमार जैन** :

श्री राम जेठमलानी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत महीनों में देश में पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया की स्थापना की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन के क्रियान्वयन के लिए 764 मिलियन डालर की एक परियोजना तैयार की गई है जो सन् 2000 तक पूरी हो जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने पर विद्युत-पारेषण के दौरान विद्युत की हानि की प्रतिशतता का क्या लक्ष्य रखा गया है तथा इस लक्ष्य और विद्युत पारेषण की वर्तमान हानि में कितना अन्तर है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू : (क) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (जो कि पहले नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के नाम से जाना जाता था) को अक्टूबर, 1989 में निगमित किया गया जिसकी आरम्भिक प्राधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रुपए थी ।

(ख) पावर ग्रिड द्वारा एक परियोजना तैयार की गई है जिसमें स्विच यार्ड सहित रामागुंडम हैदराबाद 400 कें. वी. लाइन, दक्षिणी क्षेत्र के लिए एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार परियोजना, विध्याचल चरण-I से सम्बद्ध अतिरिक्त पारेषण प्रणाली तथा अनेकों तकनीकी अध्ययन कार्य प्रमुख हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 764 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 2368 करोड़ रुपए) है । यद्यपि विश्व बैंक ने 350 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 1085 करोड़ रुपए) का ऋण स्वीकृत कर दिया है तथा शेष निधियां पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों सहित अन्य स्त्रोतों के माध्यम से जुटाई जाएंगी । परियोजना को 1999 के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की आशा है ।

(ग) अतिरिक्त उच्च वोल्टता नेटवर्क पर पारेषण हानियां बहुत ही कम हैं तथा यह संवितरण का वह पहलू है जिसमें पारेषण तथा वितरण हानियां अत्यधिक मात्रा में होती हैं । प्रस्तावित परियोजना में अतिरिक्त उच्च वोल्टता नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया जाना तथा आधुनिक प्रणाली की उन समन्वय तथा नियंत्रण सुविधाओं को कार्यान्वित किया जाना शामिल है जो कि विद्युत प्रणाली के प्रचालन की दक्षता में सुधार करेंगी । परियोजना के घटकों की जटिल प्रकृति को देखते हुए घाटों में की जाने वाली कमी की मात्रा का अनुमान लगा पाना कठिन कार्य है परन्तु कोई भी निश्चित तौर पर यह कह सकता है कि परिष्कृत प्रणाली निश्चित तौर पर पारेषण हानियों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा ।

ऊर्जा संरक्षण के लिए जनजागरण अभियान

992. **श्री वीरेन्द्र जे. शाह** :

डा. जितेन्द्र कुमार जैन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऊर्जा के स्रोतों, विशेष रूप से विद्युत के संरक्षण के लिए एक जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापारिक स्थापनाओं और घरों में उपयोग की जा रही विद्युत की क्षेत्र-वार प्रतिशतता के ब्यौरे के संबंध में कोई अनुमान लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत के संरक्षण की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत के संरक्षण के लिए किन-किन क्षेत्रों में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने वाले संरक्षण की प्रतिशतता कितनी होगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) जी हां । कुछ समय के लिए सरकार द्वारा ऊर्जा, खासतौर पर बिजली के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया जाता रहा है ।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) के अनुसार 1991-92 के दौरान बेची गई बिजली का क्षेत्रवार, अनंतिम विवरण निम्नवत् है :—

श्रेणी	1991-92 के लिए कुल बिक्री की (अनंतिम) प्रतिशतता
कृषि	28.05
उद्योग	42.30
वाणिज्यिक	5.72
घरेलू	17.16
अन्य	6.77
जोड़ :	100.00

(ग) और (घ) जी, हां । अधिक मात्रा में ऊर्जा संरक्षण किए जाने वाले कई क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा इसमें कृषि क्षेत्र के अलावा एल्युमीनियम, स्टील, गौण स्टील, कांच तथा मृत्तिका, सीमेंट, उर्वरक तथा भारी रसायन जैसी ऊर्जा की अधिक खपत वाले उद्योग शामिल हैं । घरेलू तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में भी ऊर्जा की बचत की जा सकती है । राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम निर्धारित कर दिए जाने के बाद सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऊर्जा की बचत सम्बन्धी विशेष लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया जाएगा ।

Power crisis in Delhi

993. **SHRI VITHALBHAI M. PATEL :**
SHRI RAMDAS AGARWAL :
DR. BAPU KALDATE :
SHRIMATI KAMLA SINHA :

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Hindustan Times of 21st April, 1993 Captioned "Delhi in for dark days";

(b) whether it is a fact that the Badarpur Thermal Power Station has to close down its three units of 100 MW because of lack of supply of coal ;

(c) what steps Government propose to take to ensure that uninterrupted power supply continues for citizens of Delhi; and

(d) who are responsible for the closure of three units of Badarpur Thermal Power station ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Badarpur Thermal Power Station (BTPS) had to close down its three units of 100 MW recently for a few days due to non-receipt of adequate coal supplies. The situation has arisen due to the inability of DESU to pay for the purchase of power from BTPS. Consequently the arrears for coal supply/railway freight against BTPS have been mounting and Coal India Ltd. are insisting for clearance of their dues for resuming the coal supplies. Government is making every effort to ensure adequate power supply to the Capital and Delhi Administration/DESU have been asked to find ways and means for meeting the cost of power purchase from BTPS